IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 4 October-December, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.23440060

ISSN : 3048-6971

"छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के योगदान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के संदर्भ में : एक अध्ययन"

[1] डॉ. लखेश्वर
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर (छ.ग.)

[2] डॉ. स्वाति शर्मा
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)
नवीन शासकीय महाविद्यालय,
माना कैम्प रायपुर, (छ.ग.)

[3] बोध प्रकाश राठौर
अतिथि व्याख्याता (अर्थशास्त्र)
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर (छ.ग.)

सारांश

छत्तीसगढ़ एक संसाधन–समृद्ध राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि, खनिज–आधारित उद्योग और तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के संदर्भ में इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों के योगदान, वृद्धि प्रवृत्तियों तथा परस्पर संबंधों का विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है और इसमें छत्तीसगढ़ शासन के बजट दस्तावेज, वृहद आर्थिक ढांचा विवरण, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रकाशनों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2023–24 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य के GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.32 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का 53.50 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का 31.19 प्रतिशत रहा (Government of Chhattisgarh, 2024)। वर्ष 2024–25 में स्थिर कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 5. 38, 6.92 और 8.54 प्रतिशत अनुमानित की गई (Government of Chhattisgarh, 2025a)। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य की आर्थिक संरचना औद्योगिक प्रधान है, पर रोजगार और ग्रामीण आय के लिए कृषि तथा भविष्य के विविधीकरण के लिए सेवा क्षेत्र समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दीर्घकालीन समावेशी विकास के लिए कृषि उत्पादकता, कृषि–प्रसंस्करण, रोजगार–प्रधान विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

मुख्य शब्द : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तना, (MoS&PI) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्र ।

1. प्रस्तावना

किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास गति को समझने का सबसे व्यापक सूचक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product&GSDP) है। GSDP राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह केवल आर्थिक आकार नहीं बताता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि कृषि, उद्योग और सेवाओं में उत्पादन, निवेश और आय का वितरण किस प्रकार है। विकास अर्थशास्त्र के अनुसार समय के साथ अर्थव्यवस्था सामान्यतः कृषि प्रधान संरचना से उद्योग और फिर उच्च उत्पादकता वाली सेवाओं की ओर बढ़ती है, परंतु यह परिवर्तन प्रत्येक राज्य में समान गति या समान रूप में नहीं होता है (MoS&PI) 2025)।

छत्तीसगढ़ का आर्थिक ढांचा भारत के कई राज्यों से अलग है। राज्य कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, और वन–संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यही कारण है कि खनन, धातु, ऊर्जा, सीमेंट और भारी विनिर्माण का योगदान बहुत अधिक है। दूसरी ओर, बड़ी ग्रामीण आबादी कृषि एवं संबद्ध

गतिविधियों पर निर्भर है। तीसरा आयाम सेवा क्षेत्र का है जिसमें व्यापार, परिवहन, संचार, वित्त, रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन और आधुनिक डिजिटल सेवाएँ शामिल हैं। अतः राज्य के विकास की स्थिरता तीनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रदर्शन से निर्धारित होती है।

यह अध्ययन दो मूल प्रश्नों पर केंद्रित है। पहला, GSDP में अत्यधिक औद्योगिक हिस्सेदारी राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति को किस सीमा तक दर्शाती है? दूसरा, कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार औद्योगिक उत्पादन को रोजगार, उपभोग, मानव विकास और क्षेत्रीय संतुलन से जोड़ता है? इसी आधार पर अध्ययन क्षेत्रवार योगदान, वृद्धि दर और नीतिगत महत्व का विश्लेषण करता है।

2. साहित्य समीक्षा

संरचनात्मक परिवर्तन संबंधी साहित्य यह बताता है कि विकास की प्रक्रिया में श्रम और संसाधन निम्न उत्पादकता वाली गतिविधियों से उच्च उत्पादकता वाली गतिविधियों की ओर जाते हैं। भारत में यह परिवर्तन विशिष्ट रहा है क्योंकि सेवाओं की वृद्धि कई अवधियों में विनिर्माण से तेज रही है। राज्य स्तरीय अध्ययनों में आधारभूत संरचना, प्राकृतिक संसाधन, मानव पूंजी, बाजार पहुंच और सरकारी नीति को क्षेत्रीय वृद्धि के प्रमुख निर्धारक माना गया है (Reserve Bank of India [RBI], 2025, NITI Aayog, 2024)।

छत्तीसगढ़ के सरकारी आर्थिक दस्तावेज लगातार यह दर्शाते हैं कि राज्य की उत्पादन संरचना में उद्योग की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वर्ष 2023–24 में राज्य के GSDP में उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग की हिस्सेदारी 30.97 प्रतिशत थी। इसके विपरीत राज्य में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 31.19 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 54.62 प्रतिशत थी (Government of Chhattisgarh, 2024)। यह अंतर राज्य की संसाधन–आधारित औद्योगिक संरचना को स्पष्ट करता है।

महामारी के बाद की अवधि में भी क्षेत्रीय पुनरुद्धार में उद्योग की भूमिका मजबूत रही। 2020–21 से 2021–22 के बीच वर्तमान मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 8.9, 17.3 और 11.3 प्रतिशत दर्ज की गई (Government of Chhattisgarh, 2022)। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में औद्योगिक चक्र GSDP की गति को काफी प्रभावित करता है, जबकि सेवाएं आर्थिक स्थिरता और मांग पुनरुद्धार का महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहती हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध पद्धति

इस विषय के अध्ययन के उद्देश्य हैं

(i) छत्तीसगढ़ के ळैक्च् की हाल की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।

(ii) कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी और वृद्धि दर की तुलना करना।

(iii) प्रत्येक क्षेत्र की विकासात्मक भूमिका तथा सीमाओं का विश्लेषण करना

(iv) अधिक संतुलित, रोजगार–सृजक एवं सतत आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुझाव देना।

शोध पद्धति

अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। मुख्य स्रोतों में छत्तीसगढ़ शासन के बजट 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 से संबंधित दस्तावेज, वृहद आर्थिक ढांचा विवरण, भारतीय रिजर्व बैंक के राज्यवार सांख्यिकीय प्रकाशन तथा डैव्च् के राष्ट्रीय लेखा संबंधी प्रकाशन शामिल है। अलग–अलग सरकारी प्रकाशनों में अग्रिम अनुमान, त्वरित अनुमान और संशोधित अनुमान के कारण संख्याओं में अंतर संभव है, इसलिए तुलना करते समय वर्ष और मूल्य–आधार का ध्यान रखा गया है।

4. छत्तीसगढ़ के GSDP की समग्र प्रवृत्ति

वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध आधिकारिक श्रृंखला राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। बजट 2023–24 के प्रमुख बिंदुओं में 2018–19 से 2023–24 के बीच GSDP का CAGR

लगभग 9.25 प्रतिशत दर्शाया गया (Government of Chhattisgarh, 2023)। 2020–21 में महामारी के कारण वृद्धि लगभग स्थिर रही, किन्तु 2021–22 से तेज पुनरुद्धार हुआ। यह पुनरुद्धार औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाओं के सामान्य होने से जुड़ा था।

2024–25 के लिए स्थिर कीमतों पर राज्य का GSDP 3,29,752 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया, जबकि 2023–24 में यह 3,06,712 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वास्तविक GSDP वृद्धि लगभग 7.51 प्रतिशत अनुमानित रही (Government of Chhattisgarh, 2025b)। वास्तविक वृद्धि इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल्य वृद्धि से अलग वास्तविक उत्पादन और आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन को दर्शाती है।

तालिका 1. छत्तीसगढ़ का GSDP : वर्तमान कीमतों पर प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रूपये करोड़ में)
2018-19	327106
2019-20	344648
2020-21	347752
2021-22	406415
2022-23	457608
2023-24	509043

(स्त्रोत– छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण)

5. प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) का योगदान

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका है। धान प्रमुख फसल है, परंतु दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी और लघु वनोपज भी आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2023–24 में कृषि क्षेत्र का GSDP योगदान 15.32 प्रतिशत था, जो उसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर की 14.41 प्रतिशत हिस्सेदारी से थोड़ा अधिक था (Government of Chhattisgarh, 2024)।

2024–25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर GSVA 48,987 करोड़ रुपये से बढ़कर 51,621 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 5.38 प्रतिशत रही (Government of Chhattisgarh, 2025a, 2025b)। कृषि प्रदर्शन पर वर्षा, सिंचाई, समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद, बीज–उर्वरक उपलब्धता, ग्रामीण सड़क, भंडारण और बाजार संपर्क का सीधा प्रभाव पड़ता है।

कृषि की GSDP हिस्सेदारी उद्योग की तुलना में कम है, परंतु इसे महत्वहीन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बड़ी आबादी की आजीविका, ग्रामीण मांग और खाद्य सुरक्षा का आधार है। यदि बड़ी कार्यशील आबादी अपेक्षाकृत कम मूल्यवर्धन वाले कृषि कार्य में लगी रहती है, तो प्रति श्रमिक आय सीमित रह सकती है। इसलिए राज्य में कृषि उत्पादकता के साथ कृषि–प्रसंस्करण, कोल्ड–चेन, चावल–आधारित उत्पाद, डेयरी, मत्स्य और वनोपज मूल्य श्रृंखला का विस्तार आवश्यक है।

कृषि और उद्योग के बीच मजबूत संबंध ग्रामीण आय में स्थिरता ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय प्रसंस्करण से किसानों को कच्चे उत्पाद की तुलना में बेहतर बाजार मिलता है, जबकि उद्योग को स्थिर कच्चा माल और ग्रामीण क्षेत्रों को गैर–कृषि रोजगार मिलता है। इसलिए कृषि क्षेत्र का योगदान केवल प्राथमिक उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण औद्योगिक तंत्र को सक्रिय करने में भी है।

तालिका 2. वर्ष 2023–24 में GSDP में क्षेत्रीय हिस्सेदारी

क्षेत्र	छत्तीसगढ़ (%)	भारत (%)
कृषि	15.32	14.41
उद्योग	53.50	30.97
सेवा	31.19	54.62

6. द्वितीय क्षेत्र (उद्योग क्षेत्र) का योगदान

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की सबसे विशिष्ट विशेषता उद्योग क्षेत्र की अत्यधिक उच्च हिस्सेदारी है। राज्य में खनन, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, बिजली उत्पादन, एल्यूमिनियम, स्पंज आयरन और अन्य भारी उद्योग लंबे समय से औद्योगिक आधार के केंद्र रहे हैं। वर्ष 2023–24 में ळैक्ट में उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत 30.97 प्रतिशत से बहुत अधिक था (Government of Chhattisgarh, 2024)।

2024–25 में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का GSVA 1,37,649 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,47,172 करोड़ रुपये अनुमानित हुआ और वृद्धि दर 6.92 प्रतिशत रही (Government of Chhattisgarh, 2025a; 2025b)। उद्योग राज्य के राजस्व, निर्यात, ऊर्जा उपयोग, नगरीकरण, निर्माण और परिवहन गतिविधियों को बढ़ाता है। भारी औद्योगिक निवेश से लॉजिस्टिक्स, मशीनरी रखरखाव, सुरक्षा, वित्त, व्यापार और पेशेवर सेवाओं में भी अप्रत्यक्ष मांग उत्पन्न होती है।

फिर भी उच्च औद्योगिक हिस्सेदारी को स्वतः व्यापक रोजगार के समान नहीं माना जा सकता। खनन और बड़े पूंजी–प्रधान उद्योगों में उत्पादन बहुत अधिक होता है पर प्रति इकाई निवेश प्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षाकृत सीमित हो सकता है। इसलिए औद्योगिक नीति में MSME, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना आवश्यक है।

औद्योगिक विकास की गुणवत्ता पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर भी निर्भर है। खनन, जल उपयोग, भूमि परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण औद्योगिक वृद्धि को पर्यावरणीय अनुपालन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संसाधनों के पुनर्स्थापन से जोड़ना चाहिए। स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट पुनर्चक्रण भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के भी आवश्यक अंग बन रहे हैं।

7. तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का योगदान

सेवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के GSDP में उद्योग से छोटा है, पर इसकी वृद्धि गति अधिक गतिशील दिखाई देती है। वर्ष 2023–24 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 31.19 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 54.62 प्रतिशत थी (Government of Chhattisgarh, 2024)। यह अंतर बताता है कि राज्य में आधुनिक सेवाओं, वित्त, आई.टी., पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के विस्तार की पर्याप्त संभावना है।

स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का GSVA 2023–24 के 99,925 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 में 1,08,461 करोड़ रुपये अनुमानित हुआ। 8.54 प्रतिशत की वृद्धि दर तीनों प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक थी (Government of Chhattisgarh, 2025a, 2025b)। व्यापार, होटल, परिवहन, रियल एस्टेट, वित्त, संचार, सार्वजनिक प्रशासन और सामाजिक सेवाओं की बढ़ती गतिविधियों ने इस वृद्धि को समर्थन दिया।

रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र विविध है। खुदरा व्यापार, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य और आतिथ्य बड़े पैमाने पर मध्यम कौशल रोजगार दे सकते हैं, जबकि आई.टी., डेटा सेवाएं, वित्त और पेशेवर सेवाएं उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए अवसर पैदा करती हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ कौशल विकास, उच्च शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना आवश्यक है।

सेवा क्षेत्र उद्योग और कृषि दोनों का सहायक है। बैंकिंग और बीमा कृषि निवेश को समर्थन देते हैंय परिवहन और गोदाम उद्योग तथा कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ते हैं, डिजिटल भुगतान व्यापार लागत कम करते हैं, और शिक्षा व स्वास्थ्य मानव पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र का प्रभाव उसके प्रत्यक्ष GSDP योगदान से अधिक व्यापक है।

8. तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण

उपलब्ध आंकड़ों को साथ रखने पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एक त्रिस्तरीय संरचना प्रदर्शित करती है। उद्योग उत्पादन का सबसे बड़ा स्तंभ है, सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्तंभ है और कृषि सामाजिक तथा रोजगार आधार को स्थिरता देती है। यदि विकास रणनीति केवल उद्योग पर केंद्रित रहे तो रोजगार और क्षेत्रीय आय में असंतुलन बढ़ सकता है। यदि केवल कृषि संरक्षण पर केंद्रित रहे तो उत्पादकता और आय वृद्धि सीमित रह सकती है और यदि केवल सेवाओं पर निर्भरता बढ़े तो विनिर्माण की मौजूदा ताकत का पूर्ण उपयोग नहीं होगा।

कृषि और उद्योग के बीच सबसे प्रभावी सेतु कृषि–प्रसंस्करण है। इसी प्रकार उद्योग और सेवा क्षेत्र के बीच लॉजिस्टिक्स, आई.टी., बैंकिंग, बीमा, अनुसंधान, डिजाइन, गुणवत्ता परीक्षण और व्यावसायिक सेवाएं संबंध बनाती हैं। इन अंतर्संबंधों से उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार में गुणक प्रभाव पैदा हो सकता है।

राज्य में क्षेत्रीय असमानता भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रायपुर दुर्ग–भिलाई और बिलासपुर जैसे शहरी–औद्योगिक केंद्र तथा खनिज–समृद्ध जिले आर्थिक गतिविधि के बड़े केंद्र हैं, जबकि दूरस्थ आदिवासी और ग्रामीण जिलों में बाजार पहुंच, कौशल, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं की सीमाएं हैं। जिला–विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर, ग्रामीण प्रसंस्करण, पर्यटन, वनोपज आधारित उद्यम और डिजिटल सेवाएं इस असमानता को कम कर सकती हैं।

तालिका 3. वर्ष 2024–25 में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रीय वृद्धि

क्षेत्र	छत्तीसगढ़ (%)	भारत (%)
कृषि	5.38	3.76
उद्योग	6.92	6.22
सेवा	8.54	7.22

तालिका 4. स्थिर कीमतों पर क्षेत्रीय GSVA

क्षेत्र	2023–24 (रूपये करोड़ में)	2024–25 अनुमान (रूपये करोड़ में)
कृषि	48987	51621
उद्योग	137649	147172
सेवा	99925	108461

9. क्षेत्रीय परस्पर निर्भरता और विकास के निहितार्थ

GSDP की क्षेत्रीय संरचना को अलग–अलग हिस्सों के रूप में देखने के बजाय उनके परस्पर संबंधों को समझना अधिक उपयोगी है। कृषि की आय बढ़ती है तो ग्रामीण उपभोग बढ़ता है, जिससे खुदरा व्यापार, परिवहन, निर्माण और छोटी विनिर्माण इकाइयों की मांग बढ़ती है। औद्योगिक विस्तार से मजदूरी, निर्माण, बिजली, परिवहन और वित्तीय सेवाओं की मांग बनती है। सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, संचार और डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से कृषि और उद्योग दोनों की उत्पादकता बढ़ाता है। इसलिए किसी एक क्षेत्र की वृद्धि दूसरे क्षेत्र की मांग और निवेश को प्रभावित करती है।

छत्तीसगढ़ के लिए इस परस्पर निर्भरता का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य में एक और संसाधन–आधारित बड़े उद्योग हैं और दूसरी ओर व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि बड़े उद्योगों की स्थानीय खरीद, कौशल प्रशिक्षण और डैडम् आपूर्ति श्रृंखला मजबूत की जाए तो औद्योगिक GSDP का लाभ स्थानीय आय में अधिक प्रभावी रूप से प्रसारित हो सकता है। इसी तरह कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को शहरी बाजारों, ई–कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स से जोडकर कृषि को सेवा और उद्योग दोनों से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार विकास रणनीति का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय हिस्सेदारी बदलना नहीं, बल्कि उत्पादक अन्तर सबंधों को गहरा करना होना चाहिए।

10. विचार– विमर्श/उल्लेख

उपलब्ध आंकड़े यह दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल अभी भी संसाधन–आधारित औद्योगीकरण से गहराई से जुड़ा है। यह स्थिति राज्य को उच्च औद्योगिक उत्पादन का लाभ देती है, लेकिन विकास की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इस उत्पादन से प्राप्त आय कितनी व्यापक रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था में फैलती है। यदि खनन और भारी उद्योग अपने कच्चे माल, मशीनरी, रखरखाव, परिवहन और सेवाओं के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करते हैं, तो उनकी GSDP हिस्सेदारी का प्रभाव रोजगार और उद्यमिता पर अधिक व्यापक होगा। यदि ऐसा संबंध कमजोर रहता है, तो उच्च औद्योगिक

GSDP के बावजूद क्षेत्रीय असमानता और रोजगार की सीमाएं बनी रह सकती हैं। सेवा क्षेत्र की तेज वृद्धि राज्य के लिए संरचनात्मक परिवर्तन का दूसरा मार्ग प्रस्तुत करती है। आधुनिक सेवाएं अपेक्षाकृत कम प्राकृतिक संसाधन उपयोग के साथ उच्च मूल्यवर्धन उत्पन्न कर सकती हैं। नवा रायपुर और अन्य शहरी केंद्रों में, आई.टी.,स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, लॉजिस्टिक्स, डेटा और पेशेवर सेवाओं का विस्तार राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक विविध बना सकता है। किंतु यह वृद्धि समावेशी तभी होगी जब स्थानीय युवाओं के कौशल को उद्योग की मांग के अनुरूप विकसित किया जाए और छोटे शहरों में डिजिटल तथाए शहरी अवसंरचना का विस्तार हो।

कृषि क्षेत्र का विश्लेषण यह भी संकेत करता है कि GSDP हिस्सेदारी और सामाजिक महत्व हमेशा समान नहीं होते। कृषि का आर्थिक हिस्सा उद्योग से बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण परिवारों की आय, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय मांग पर उसका प्रभाव विशाल है। अतः कृषि में उत्पादकता वृद्धि का प्रभाव प्रत्यक्ष GSDP से आगे जाकर व्यापार, परिवहन, निर्माण और छोटी सेवाओं तक पहुंचता है। इसी कारण कृषि को केवल प्राथमिक क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि ग्रामीण मांग और स्थानीय औद्योगीकरण के आधार के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है।

तीनों क्षेत्रों के संयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ के लिए सर्वोत्तम विकास मार्ग 'कृषि बनाम उद्योग' या 'उद्योग बनाम सेवाएं' का चुनाव नहीं, बल्कि उनके बीच उत्पादक संबंधों को मजबूत करना है। कृषि–प्रसंस्करण, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स, डिजिटल बाजार, कौशल सेवाएं, स्थानीय वित्त और तकनीकी समर्थन जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों को जोड़ती हैं। इस प्रकार GSDP वृद्धि को रोजगार, आय और मानव विकास में बदलने के लिए अंतःक्षेत्रीय को विकास नीति का केंद्रीय आधार बनाया जाना चाहिए।

11. निष्कर्षात्मक बिन्दु

इस विषय में विचार विमर्श के अध्ययन से पाँच प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं –

1. छत्तीसगढ़ का GSDP महामारी के बाद पुनः मजबूत वृद्धि पथ पर आया है और 2024–25 में वास्तविक वृद्धि लगभग 7.5 प्रतिशत अनुमानित की गई।
2. उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी अत्यधिक ऊंची है, जो राज्य की खनिज और भारी उद्योग आधारित संरचना को दर्शाती है।
3. कृषि की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद रोजगार, ग्रामीण आय और सामाजिक स्थिरता में उसकी भूमिका व्यापक है।
4. सेवा क्षेत्र हाल में सबसे तेज बढ़ता क्षेत्र है और भविष्य के विविधीकरण का प्रमुख स्रोत बन सकता है।
5. दीर्घकालीन विकास की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि बड़े औद्योगिक उत्पादन को स्थानीय MSME, कृषि मूल्य श्रृंखला और आधुनिक सेवाओं से कितना जोड़ा जाता है।

12. नीतिगत सुझाव

1. कृषि क्षेत्र में सिंचाई दक्षता, जल–संरक्षण, भंडारण, किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण और बाजार पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धान के साथ, दलहन, तिलहन, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य को भी आय वृद्धि की रणनीति में समान स्थान देना उपयोगी होगा।
2. उद्योग क्षेत्र में बड़े पूंजी निवेश के साथ रोजगार–प्रधान विनिर्माण और MSME को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय विक्रेता विकास, तकनीकी उन्नयन, कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक क्लस्टर से बड़े उद्योगों का स्थानीय गुणक प्रभाव बढ़ाया जा सकता है।
3. सेवा क्षेत्र के लिए नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग–भिलाई और बिलासपुर को आई.टी. स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और पेशेवर सेवाओं के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। दूरस्थ जिलों में डिजिटल कनेक्टिविटी, ई–सेवाएं, पर्यटन और वन–आधारित उद्यम रोजगार का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं।

4. GSDP वृद्धि के साथ रोजगार, श्रम उत्पादकता, प्रति व्यक्ति आय, जिला–स्तरीय असमानता, महिला श्रम भागीदारी और पर्यावरणीय गुणवत्ता जैसे संकेतकों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। इससे विकास की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता का भी आकलन संभव होगा।

13. अध्ययन की सीमाएं

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और इसलिए इसकी निष्कर्ष–सीमा उपलब्ध सरकारी प्रकाशनों तक है। GSDP और GSVA के आंकड़े समय के साथ अग्रिम अनुमान, त्वरित अनुमान तथा संशोधित अनुमान के रूप में बदल सकते हैं। अलग–अलग बजट दस्तावेजों में मूल्य–आधार और संशोधन स्तर के कारण एक ही वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में मामूली अंतर मिलना स्वाभाविक है। इस अध्ययन ने तुलनात्मक व्याख्या करते समय आधिकारिक स्रोत–वर्ष को प्राथमिकता दी है, किंतु अंतिम संशोधित श्रृंखला उपलब्ध होने पर संख्यात्मक निष्कर्षों को पुनः जांचना आवश्यक होगा।

दूसरी सीमा यह है कि क्षेत्रीय GSDP किसी क्षेत्र के रोजगार, आय–वितरण या सामाजिक प्रभाव का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। उद्योग क्षेत्र की ऊंची हिस्सेदारी उच्च उत्पादन को दर्शाती है, पर उससे रोजगार की संख्या, वेतन की गुणवत्ता और स्थानीय मूल्यवर्धन का स्वतः पता नहीं चलता। इसी प्रकार कृषि की कम GSDP हिस्सेदारी के बावजूद उसमें बड़ी आबादी निर्भर हो सकती है। इसलिए भविष्य के अध्ययन में PLFS रोजगार आंकड़े, जिला–स्तरीय आय, महिला श्रम भागीदारी, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक रोजगार को GSDP विश्लेषण से जोड़ना अधिक उपयोगी होगा।

14. निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रधान है, पर उसका दीर्घकालीन विकास कृषि, उद्योग और सेवाओं के संतुलित तथा परस्पर पूरक विस्तार पर निर्भर है। GSDP के आंकड़े बताते हैं कि उद्योग उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है और सेवा क्षेत्र तेजी से उभर रहा है, जबकि कृषि लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन और आय का आधार बनी हुई है। इसलिए नीति का उद्देश्य केवल GSDP बढ़ाना नहीं, बल्कि क्षेत्रों के बीच मूल्य श्रृंखला, कौशल, तकनीक, स्थानीय उद्यमिता और रोजगार संबंधों को मजबूत करना होना चाहिए। ऐसा करने पर छत्तीसगढ़ संसाधन–आधारित विकास से अधिक विविध, उत्पादक, समावेशी और सतत आर्थिक संरचना की ओर बढ़ सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Government of Chhattisgarh, Department of Finance. (2024), Budget 2024-25. Press note.
2. Government of Chhattisgarh, Department of Finance. (2025a). Key highlights: Budget 2025-26.
3. Government of Chhattisgarh, Department of Finance. (2025b). Macroeconomic framework statement, 2025-26.
4. Government of Chhattisgarh, Department of Finance. (2026). Budget 2026-27- Press note and budget documents.
5. Government of Chhattisgarh, Directorate of Economics and Statistics. (2025). State Income estimates and sectoral statistics.
6. Ministry of Finance, Government of India (2026). Economic Survey 2025-26.
7. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2025). National accounts statistics and selected indicators of the Indian economy
8. NITI Aayog. (2024). SDG India index and dashboard 2023-24.
9. Reserve Bank of India. (2025). Handbook of statistics on Indian states.
10. Reserve Bank of India. (2024). State finances. A study of budgets.
11. Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2025). Agricultural statistics at a glance
12. Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2025). Annual report 2024-25.
13. Government of India, Ministry of Commerce & Industry. (2025). Annual survey of industries and industrial statistics.
14. World Bank. (2024). India development update.
15. International Labour Organization. (2024). India employment report 2024. Youth employment, education and skills.
16. Vimla Nawariya.(2025). Assessing the Economic Transformation of chhattisgarh: A Historical Perspective,
17. Prachee Sharma.(2024) A Study on Sectoral Development, Growth and challenges in chhattisgarh.